



Lakshya IAS

academy

20

Aug 2026

DAILY CURRENT AFFAIRS



Mr. R.P. Singh Sir
(MD)



1. राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025

सरकार ने 18 अगस्त को एथलेटिक उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा की। प्रमुख महिला बैडमिंटन युगल जोड़ी ट्रेसी जॉली और पुल्लेला गायत्री गोपीचंद, विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करेंगी। अनुभवी भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी इसैया अरुमइनायगम को अर्जुन पुरस्कार (लाइफटाइम) से सम्मानित किया जाएगा। कोचिंग के क्षेत्र में, द्रोणाचार्य पुरस्कार परवीर सिंह (एथलेटिक्स), छोटे लाल यादव (बॉक्सिंग) और नेहा नंदकुमार चव्हाण (शूटिंग) को प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पुणे स्थित आर्मी पैरालिंपिक नोड को खेल संवर्धन और विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त होगा।

मुख्य बिंदु:

- अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता: बैडमिंटन युगल जोड़ी ट्रेसी जॉली और पुल्लेला गायत्री गोपीचंद अर्जुन पुरस्कार के लिए चुने गए 17 एथलीटों में शामिल हैं, जबकि अनुभवी फुटबॉल खिलाड़ी इसैया अरुमइनायगम को अर्जुन पुरस्कार (लाइफटाइम) प्राप्त होगा।
- द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता: कोच परवीर सिंह (एथलेटिक्स), छोटे लाल यादव (बॉक्सिंग) और नेहा नंदकुमार चव्हाण (शूटिंग) को कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए चुना गया।

1. National Sports Awards 2025

The Government announced the National Sports Awards 2025 to recognize and reward athletic excellence on 18th August. Premier women's badminton doubles pair Treesa Jolly and Pullela Gayatri Gopichand, along with 15 other sportspersons across various disciplines, will receive the Arjuna Award for outstanding performance. Veteran Indian footballer Isaiah Arumainayagam is set to be honored with the Arjuna Award (Lifetime). In coaching, the Dronacharya Award will be presented to Parveer Singh (Athletics), Chhote Lal Yadav (Boxing), and Neha Nandkumar Chavan (Shooting). Additionally, the Army Paralympic Node in Pune will receive the Rashtriya Khel Protsahan Puruskar for its significant contributions toward sports promotion and development.

Key points:

- Arjuna Award Recipients: Badminton doubles duo Treesa Jolly and Pullela Gayatri Gopichand are among 17 athletes selected for the Arjuna Award, while veteran footballer Isaiah Arumainayagam receives the Arjuna Award (Lifetime).
- Dronacharya Awardees: Coaches Parveer Singh (Athletics), Chhote Lal Yadav (Boxing), and Neha Nandkumar Chavan (Shooting) were chosen for excellence in coaching.

- राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार: खेल को बढ़ावा देने और विकसित करने में सक्रिय भूमिका के लिए आर्मी पैरालिंपिक नोड, पुणे को सम्मानित किया गया।

2. ऑल इंडिया गर्ल्स हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग ट्रेक 'अपराजिता - पारंग ला 2026' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार 18 अगस्त को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के प्रमुख साहसिक अभियान, 'अपराजिता - पारंग ला 2026' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 30 दिनों की यह ट्रेकिंग यात्रा चुनौतीपूर्ण पारंग ला दर्रे से होकर 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो हिमाचल प्रदेश की स्पिति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ती है। तीनों सेनाओं की तीन महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 महिला कैडेटों का एक दल इस उच्च-स्तरीय ट्रेक में भाग ले रहा है। कैडेटों की शारीरिक और मानसिक तैयारी की सराहना करते हुए, रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे अभियानों में भागीदारी भारतीय महिलाओं के साहस और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है, साथ ही यह नेतृत्व, मानसिक दृढ़ता, अनुशासन और आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है। उन्होंने यात्रा के दौरान सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता को प्राथमिकता देने की सलाह दी।



मुख्य बिंदु:

- हरी झंडी दिखाई: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली से 'अपराजिता - पारंग ला 2026' नामक एनसीसी ऑल इंडिया गर्ल्स हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग ट्रेक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
- मार्ग और अवधि: 30 दिवसीय यह अभियान पारंग ला दर्रे से होते हुए 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जो हिमाचल प्रदेश की स्पिति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है।
- प्रतिभागी: इस टीम में थल सेना, नौसेना और वायु सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली तीन महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 एनसीसी महिला कैडेट शामिल हैं।

- Rashtriya Khel Protsahan Puruskar: Awarded to the Army Paralympic Node, Pune for its active role in promoting and developing sports.

2. All India Girls High Altitude Long Trek 'Aparajita - Parang La 2026' flagged off

- Defence Minister Rajnath Singh flagged off the National Cadet Corps (NCC) flagship adventure expedition, "Aparajita - Parang La 2026," in New Delhi on Tuesday August 18. The 30-day trek covers 250 kilometers across the challenging Parang La Pass, connecting Himachal Pradesh's Spiti Valley with Ladakh's Changthang region. A contingent of 28 girl cadets, led by three women officers from the tri-services, is participating in this high-altitude trek. Commending the cadets' physical and mental preparation, the Defence Minister highlighted that participation in such expeditions reflects the courage and growing capabilities of Indian women, while fostering leadership, mental resilience, discipline, and self-confidence. He advised the team to prioritize safety, environmental preservation, and community engagement throughout the journey.



Key points:

- Flagged Off by: Defence Minister Rajnath Singh flagged off the flagship NCC All India Girls High Altitude Long Trek named "Aparajita - Parang La 2026" from New Delhi.
- Route and Duration: The 30-day expedition covers 250 kilometers through the Parang La Pass, bridging the Spiti Valley in Himachal Pradesh with the Changthang region of Ladakh.
- Participants: The team comprises 28 NCC girl cadets led by three female officers representing the Indian Army, Navy, and Air Force.

3. भारत ने घास के मैदानों के लिए पहली गाइड जारी की

भारत ने 17 अगस्त को मंगोलिया के उलानबातार में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीसीडी) के पक्षों के 17वें



सम्मेलन (सीओपी17) के दौरान भारत का पहला रंगाइड टू ग्रासलैंड्स एंड द ओपन नेचुरल इकोसिस्टम्स (ओएनई) ऑफ इंडिया जारी किया। यह व्यापक गाइड भारत के विविध खुले प्राकृतिक परिदृश्यों का विवरण प्रदान करती है, जिसमें हिमालयी और तराई के घास के मैदान, थार और बन्नी के परिदृश्य, दक्कन के सवाना, चट्टानी पठार और झाड़ीदार भूमि शामिल हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र वन्यजीव जैव विविधता, कार्बन भंडारण, मृदा और जल संरक्षण तथा जलवायु सहनशीलता का समर्थन करने के साथ-साथ पशुपालक और ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह प्रकाशन इन पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील बायोम के संरक्षण, पुनर्प्राप्ति और सतत प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए एक विज्ञान-आधारित रूपरेखा प्रदान करता है।

मुख्य बिंदु:

- पहली गाइड: भारत ने अपनी पहली समर्पित गाइड का अनावरण किया, जो सवाना, रेगिस्तान, खड्डों और झाड़ीदार भूमियों को शामिल करते हुए घास के मैदानों और खुले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों (ओएनई) का मानचित्रण करती है।
- वैश्विक लॉन्च प्लेटफॉर्म: यह गाइड मंगोलिया के उलानबातार में आयोजित यूएनसीसीडी के पक्षों के 17वें सम्मेलन (सीओपी17) में जारी की गई।
- पारिस्थितिक और आजीविका प्रभाव: यह पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्प्राप्ति, कार्बन भंडारण, जलवायु सहनशीलता बढ़ाने और पशुपालक एवं कृषि समुदायों की सुरक्षा के लिए एक वैज्ञानिक रूपरेखा प्रदान करती है।

3. India Launches First Guide to Grasslands

India launched its first-ever "Guide to Grasslands and Other Open Natural Ecosystems (ONEs) of



India" during the 17th Session of the Conference of the Parties (COP17) to the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) in Ulaanbaatar, Mongolia on 17th August. The comprehensive guide details India's diverse open natural landscapes, including the Himalayan and Terai grasslands, Thar and Banni landscapes, Deccan savannas, rocky plateaus, and scrublands. These ecosystems play a vital role in supporting wildlife biodiversity, carbon storage, soil and water conservation, and climate resilience, while sustaining pastoral and rural livelihoods. The publication provides a science-based framework to guide national efforts toward conserving, restoring, and sustainably managing these ecologically sensitive biomes.

Key points:

- First-Ever Guide: India unveiled its first dedicated guide mapping grasslands and Open Natural Ecosystems (ONEs), encompassing savannas, deserts, ravines, and scrublands.
- Global Launch Platform: The guide was released at the 17th Conference of the Parties (COP17) of the UNCCD held in Ulaanbaatar, Mongolia.
- Ecological and Livelihood Impact: It offers a scientific framework to restore ecosystems, store carbon, enhance climate resilience, and protect pastoral and agricultural communities.

4. भारत ने दो एमक्यू-9 बी सी गार्जियन मानवरहित विमान प्रणालियों को लीज पर लेने के लिए 1,943 करोड़ रुपये के सौदे पर हस्ताक्षर किए

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए दो एमक्यू-9बी सी गार्जियन हाई-एल्टीट्यूड लॉन्ग-एंड्योरेंस (हेल) रिमोटली पायलेटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम



लीज पर लेने के लिए 17 अगस्त को अमेरिका स्थित जनरल एटॉमिक्स एयरोनॉटिकल सिस्टम्स, आईएनसी. (जीए-एसआई) के साथ 1,943 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 में हस्ताक्षरित यह समझौता 30 महीने की अवधि के लिए है। उन्नत सेंसर और अत्याधुनिक पेलोड से लैस, ये मानवरहित विमान प्रणालियां भारत की समुद्री क्षेत्र जागरूकता (एमडीए) को काफी बढ़ाएंगी। विशाल महासागरीय क्षेत्रों में निरंतर खुफिया, निगरानी और टोही (आईएसआर) कवरेज प्रदान करके, यह समावेश भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर नज़र रखने और हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने की क्षमता को मजबूत करेगा।

मुख्य बिंदु:

- अनुबंध का विवरण: रक्षा मंत्रालय ने 30 महीनों के लिए दो एमक्यू-9बी सी गार्जियन ड्रोन लीज पर लेने के लिए जनरल एटॉमिक्स एयरोनॉटिकल सिस्टम्स, आईएनसी. (जीए-एसआई) के साथ 1,943 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- विमान का प्रकार: एमक्यू-9बी सी गार्जियन एक हाई-एल्टीट्यूड लॉन्ग-एंड्योरेंस (हेल) रिमोटली पायलेटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपास) है।
- रणनीतिक उद्देश्य: इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र जागरूकता (एमडीए) को बढ़ावा देना और हिंद महासागर क्षेत्र में निरंतर खुफिया, निगरानी और टोही (आईएसआर) क्षमताएं प्रदान करना है।

India inks Rs 1,943 crore deal to lease two MQ-9B sea guardian unmanned aircraft systems

The Ministry of Defence (MoD) signed a Rs 1,943 crore contract on 17th August with US-based General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) to lease two MQ-9B Sea Guardian High-Altitude Long-Endurance (HALE) Remotely Piloted Aircraft Systems for the Indian Navy. Signed at Kartavya Bhawan-2 in New Delhi, the agreement spans a tenure of 30 months. Equipped with advanced sensors and state-of-the-art payloads, these unmanned aircraft systems will significantly enhance India's Maritime Domain Awareness (MDA). By providing persistent Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) coverage over vast oceanic stretches, the induction will strengthen the Indian Navy's ability to monitor developments and respond effectively to emerging security challenges across the Indian Ocean Region.



Key points:

- Contract Details: Ministry of Defence signed a Rs 1,943 crore agreement with General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) to lease two MQ-9B Sea Guardian drones for 30 months.
- Aircraft Type: The MQ-9B Sea Guardian is a High-Altitude Long-Endurance (HALE) Remotely Piloted Aircraft System (RPAS).
- Strategic Objective: Designed to boost Maritime Domain Awareness (MDA) and deliver continuous Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) capabilities across the Indian Ocean Region.

5. भारतीय शांतिसैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक प्राप्त हुआ

दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (यूएनएमआईएसएस) में सेवा दे रहे कुल 210 भारतीय शांतिसैनिकों को 17 अगस्त को जुबा में प्रतिष्ठित



संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। सम्मानित किए गए दल में छह महिला कर्मी और सात स्टाफ अधिकारी शामिल थे, जिन्हें क्षेत्रीय शांति बनाए रखने में उनकी समर्पित सेवा और योगदान के लिए मान्यता दी गई। दक्षिण सूडान की स्वतंत्रता के बाद 2011 में स्थापित यूएनएमआईएसएस का मुख्य ध्यान नागरिकों की सुरक्षा, मानवीय सहायता की सुविधा और राष्ट्रीय शांति प्रक्रिया का समर्थन करने पर है। भारत वैश्विक संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में दूसरा सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता बना हुआ है, जिसने 1948 से अब तक 49 मिशनों में 2,00,000 से अधिक सैन्य और पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। यह सम्मान संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति अभियानों और मानवीय सहायता प्रयासों के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु:

- पुरस्कार सम्मान: जुबा, दक्षिण सूडान में कुल 210 भारतीय शांतिसैनिकों (6 महिलाओं और 7 स्टाफ अधिकारियों सहित) को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया।
- मिशन का विवरण: ये शांतिसैनिक यूएनएमआईएसएस (दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन) के तहत सेवा दे रहे हैं, जिसकी स्थापना 2011 में नागरिकों की सुरक्षा और शांति प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए की गई थी।
- भारत का योगदान: भारत 49 वैश्विक मिशनों में भाग लेते हुए, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में वर्दीधारी कर्मियों का दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश है।

5. Indian Peacekeepers Receive UN Medal

A total of 210 Indian peacekeepers serving with the United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) were honored with the prestigious United Nations Medal in Juba on 17 August. The awarded contingent included six women personnel and seven staff officers recognized for their dedicated service and contributions to maintaining regional peace. Established in 2011 following South Sudan's independence, UNMISS focuses on civilian protection, facilitating humanitarian assistance, and supporting the national peace process. India remains the second-largest troop contributor to global UN peacekeeping operations, having deployed over 200,000 military and police personnel across 49 missions since 1948. This recognition underlines India's continued commitment to international security, peacekeeping operations, and humanitarian aid efforts in conflict-affected zones.



Key points:

- Award Honor:** A total of 210 Indian peacekeepers (including 6 women and 7 staff officers) were awarded the United Nations Medal in Juba, South Sudan.
- Mission Overview:** The peacekeepers serve under UNMISS (United Nations Mission in South Sudan), which was established in 2011 to protect civilians and support the peace process.
- India's Contribution:** India is the second-largest contributor of uniformed personnel to UN peacekeeping missions, having participated in 49 missions globally.

6. भारत सेमीकॉन इंडिया 2026 की मेजबानी करेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को यशोभूमि, नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 के पांचवें संस्करण का उद्घाटन करेंगे, जिसका विषय



रसिलिकॉन टू सिस्टम्स: बिल्डिंग द इकोसिस्टम है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (माइटी) तथा सेमी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह तीन दिवसीय कार्यक्रम 40 देशों के वैश्विक उद्योग नेताओं, नीति निर्माताओं, स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को एक साथ लाता है। भारत की प्रगति को रेखांकित करते हुए, सेमीकॉन 1.0 के तहत स्वीकृत 12 परियोजनाओं में से तीन ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है, और इसके साथ ही सेमीकॉन 2.0 पहल की शुरुआत भी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, 332 शैक्षणिक संस्थानों और 105 स्टार्टअप्स को डिजाइन टूल्स वितरित किए गए हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन में भारत की स्थिति को मजबूत करना है, जिससे भारत के घरेलू सेमीकंडक्टर बाजार के 100 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 200 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।

मुख्य बिंदु:

- कार्यक्रम और विषय: सेमीकॉन इंडिया 2026 का 5वां संस्करण यशोभूमि, नई दिल्ली में रसिलिकॉन टू सिस्टम्स: बिल्डिंग द इकोसिस्टम विषय के तहत आयोजित किया जा रहा है।
- आयोजक: इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (माइटी) तथा वैश्विक उद्योग संघ सेमी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित।
- प्रगति का पड़ाव: सेमीकॉन 1.0 के तहत 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 3 ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है, जिससे सरकार की सेमीकॉन 2.0 पहल का रास्ता साफ हो गया है।

6. India to Host SEMICON India 2026

Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the fifth edition of SEMICON India 2026 at Yashobhoomi, New Delhi on September 17, themed "Silicon to Systems: Building the Ecosystem." Jointly organized by the India Semiconductor Mission (ISM), MeitY, and SEMI, the three-day event brings together global industry leaders, policymakers, startups, and researchers across 40 countries. Highlighting India's progress, three out of twelve approved projects under Semicon 1.0 have started commercial production, alongside the rollout of the Semicon 2.0 initiative. Additionally, design tools have been distributed to 332 academic institutes and 105 startups. The conference aims to strengthen India's position in semiconductor design, manufacturing, and supply chain resilience, projecting India's domestic semiconductor market to grow from USD 100 billion to USD 200 billion.



Key points:

- Event and Theme: The 5th edition of SEMICON India 2026 is held at Yashobhoomi, New Delhi, under the theme "Silicon to Systems: Building the Ecosystem."
- Organizers: Jointly hosted by the India Semiconductor Mission (ISM), Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), and global industry association SEMI.
- Progress Milestone: Under Semicon 1.0, 12 projects have been approved, with 3 commencing commercial production, paving the way for the government's Semicon 2.0 initiative.

7. झारखंड सरकार ने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द की

रांची में 24 दिनों से चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद, झारखंड सरकार ने सोमवार 17 अगस्त को निजी परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल द्वारा आयोजित जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा सहित सभी भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई एक विशेष कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया। भर्ती अनियमितताओं को दूर करने के लिए, राज्य सरकार ने 2014 से जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं की व्यापक जांच के आदेश दिए। इसके अतिरिक्त, राज्य की परीक्षा प्रणाली में सुधारों की सिफारिश करने के लिए आईएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक सुधार समिति का गठन किया गया। हालांकि प्रदर्शनकारी छात्रों ने परीक्षा रद्द किए जाने का स्वागत किया और अपना आंदोलन स्थगित कर दिया, लेकिन छात्र नेताओं ने दोहराया कि सीबीआई जांच शुरू होने तक विरोध जारी रहेगा। इस बीच, पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी नौकरी की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की।



मुख्य बिंदु:

- परीक्षा रद्द: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट ने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया।
- सिस्टम की जांच: राज्य ने 2014 से जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की जांच के आदेश दिए हैं।
- सुधार समिति: राज्य के परीक्षा संचालन ढांचे में संरचनात्मक सुधारों का सुझाव देने के लिए आईएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

7. Jharkhand govt cancels JSSC-CGL exam

Following a 24-day student protest in Ranchi, the Jharkhand government, on Monday 17 August, cancelled the JSSC-CGL examination along with all recruitment exams conducted by the private testing agency TDPL. The decision was finalized during a special Cabinet meeting chaired by Chief Minister Hemant Soren. To address recruitment irregularities, the state government ordered a comprehensive probe into exams conducted by JPSC and JSSC since 2014. Additionally, a reform committee headed by IAS officer Amitabh Kaushal was constituted to recommend improvements to the state's examination system. While protesting students welcomed the cancellation and suspended their agitation, student leaders affirmed that protests would persist until a CBI probe is initiated. Meanwhile, previously selected candidates expressed deep concern regarding their job security.



Key points:

- Exam Cancellation: The Jharkhand Cabinet chaired by CM Hemant Soren cancelled the JSSC-CGL exam and all recruitment exams conducted by private agency TDPL.
- Systemic Probe: The state ordered an investigation into all competitive examinations conducted by JPSC and JSSC since 2014.
- Reform Committee: An expert committee headed by IAS officer Amitabh Kaushal has been formed to suggest structural reforms in the state's exam conduct framework.

8. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का उद्घाटन किया

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 17 अगस्त को देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित हिमाद्रि आइस रिंग में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का उद्घाटन किया।



चार दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में 14 एशियाई देशों के 270 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें 130 सदस्यीय भारतीय दल भी शामिल है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि लगातार दूसरे वर्ष इस चैम्पियनशिप की मेजबानी करना शीतकालीन और बर्फ के खेलों के लिए एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में उत्तराखंड के कद को मजबूत करता है। राज्य की पहलों पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने उल्लेख किया कि उत्तराखंड आठ शहरों में 23 खेल अकादमियां स्थापित करने के लिए स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान लागू कर रहा है, जिसके साथ ही हल्द्वानी में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में एक महिला खेल कॉलेज भी स्थापित किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु:

- आयोजन स्थल और मेजबान: उत्तराखंड के देहरादून स्थित हिमाद्रि आइस रिंग (महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स) में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उद्घाटन किया गया।
- भागीदारी: मेजबान देश भारत के 130 प्रतिभागियों सहित 14 एशियाई देशों के 270 से अधिक एथलीट शामिल हैं।
- स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान: राज्य की खेल संवर्धन पहल के तहत, उत्तराखंड 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियां और हल्द्वानी में अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बना रहा है।

Uttarakhand CM inaugurates Asian Open Short Track Speed Skating Trophy 2026

Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami inaugurated the



Asian Open Short Track Speed Skating Trophy 2026 at the Himadri Ice Rink, Maharana Pratap Sports Complex in Dehradun on August 17th. The four-day international event features over 270 players from 14 Asian countries, including a 130-member Indian contingent. CM Dhami stated that hosting the championship for the second consecutive year reinforces Uttarakhand's stature as a premier global hub for winter and ice sports. Highlighting state initiatives, he noted that Uttarakhand is implementing a "Sports Legacy Plan" to establish 23 sports academies across eight cities, along with setting up the state's first sports university in Haldwani and a Women's Sports College in Lohaghat.

Key points:

- Event Location and Host: Inaugurated by CM Pushkar Singh Dhami at the Himadri Ice Rink (Maharana Pratap Sports Complex) in Dehradun, Uttarakhand.
- Participation: Features over 270 athletes from 14 Asian nations, including 130 participants from host nation India.
- Sports Legacy Plan: Under the state's sports promotion initiative, Uttarakhand plans to establish 23 sports academies in 8 major cities and its first sports university in Haldwani.

9. सीड योजना के माध्यम से विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को सरकार ने दी मजबूती

सामाजिक न्याय और अधिकारिता

मंत्रालय अगस्त 2026 में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (डीएनटी, एनटी, एसएनटी) के



उत्थान के लिए सीड (डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना) को लागू कर रहा है। पांच वर्षों में 200 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ 2022 में शुरू की गई सीड योजना चार प्रमुख घटकों को एकीकृत करती है: प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जय) के तहत स्वास्थ्य बीमा, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका सहायता, और प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत आवास सहायता। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लागू की गई यह योजना इन समुदायों के ऐतिहासिक सामाजिक और आर्थिक हाशियाकरण को संबोधित करती है, जिससे पूरे भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, टिकाऊ आय और सुरक्षित आवास तक उनकी पहुंच बढ़ती है।

मुख्य बिंदु:

- लक्षित लाभार्थी: आधिकारिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा न रखने वाले विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (डीएनटी, एनटी और एसएनटी) के लिए डिज़ाइन किया गया।
- नोडल मंत्रालय और शुभारंभ: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पांच वर्षों (2021-26) में 200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2022 में शुरू किया गया।
- चार मुख्य स्तंभ: मुफ्त प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग, पीएम-जय स्वास्थ्य कवरेज, आजीविका सहायता और पीएमएवाई आवास सहायता प्रदान करता है।

9. Government Strengthens Welfare and Economic Empowerment of DNT, NT and SNT through SEED Scheme

The Ministry of Social

Justice and Empowerment is implementing the SEED (Scheme for Economic Empowerment of DNTs) to



uplift De-notified, Nomadic, and Semi-Nomadic Tribes (DNTs, NTs, SNTs) in August 2026. Launched in 2022 with a Rs 200 crore budget allocation over five years, SEED integrates four key components: free coaching for competitive exams, health insurance under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY), livelihood support via self-help groups, and housing assistance under Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY). Implemented through a dedicated online portal to ensure direct benefit transfers, the scheme addresses the historical social and economic marginalization of these communities, enhancing their access to education, healthcare, sustainable income, and secure housing across India.

Key points:

- Target Beneficiaries: Designed for De-notified, Nomadic, and Semi-Nomadic Tribes (DNTs, NTs, and SNTs) lacking official SC/ST/OBC status.
- Nodal Ministry and Launch: Launched in 2022 by the Ministry of Social Justice and Empowerment with a Rs 200 crore outlay over five years (2021-26).
- Four Core Pillars: Provides free competitive exam coaching, PM-JAY health coverage, livelihood support, and PMAY housing assistance.

10. भारत और आर्मेनिया ने रक्षा नवाचार पर समझौता

ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारत और आर्मेनिया ने रक्षा अनुसंधान, विकास, नवाचार और संयुक्त उत्पादन में सहयोग को बढ़ावा



देने के लिए 17 अगस्त को येरेवन में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान भारतीय रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और आर्मेनिया के उच्च तकनीक उद्योग मंत्री दवित तादेवोस्यान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता सीधे हथियारों की बिक्री से आगे बढ़कर सहयोगात्मक निर्माण और तकनीकी एकीकरण की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है। बढ़ते संबंधों ने 2020 से दोनों देशों के बीच रक्षा अनुबंधों के कुल मूल्य को लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा दिया है। आर्मेनिया की सैन्य सूची में पहले से ही आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार और एडवांस्ड टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम (एटीएजीएस) जैसे उन्नत भारतीय प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

मुख्य बिंदु:

- रणनीतिक समझौता: येरेवन में रक्षा अनुसंधान, विकास, नवाचार और संयुक्त उत्पादन पर केंद्रित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता: भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और आर्मेनिया के उच्च तकनीक उद्योग मंत्री दवित तादेवोस्यान द्वारा हस्ताक्षरित।
- बढ़ती खरीद: आकाश, पिनाका और एटीएजीएस जैसी प्रमुख भारतीय प्रणालियों के साथ दोनों देशों के बीच रक्षा अनुबंध लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गए हैं।



10. India and Armenia Sign MoU on Defence Innovation

India and Armenia signed a landmark Memorandum of Understanding (MoU) in Yerevan on 17 August to bolster cooperation in defence research, development, innovation, and joint production. The agreement was signed by Indian Defence Secretary Rajesh Kumar Singh and Armenia's Minister of High-Tech Industry Davit Tadevosyan during an official two-day visit. The pact marks a strategic transition from direct arms sales toward collaborative manufacturing and technological integration. Expanding ties have brought the cumulative value of defence contracts between the two nations close to USD 2 billion since 2020. Armenia's military inventory already includes advanced Indian platforms such as the Akash surface-to-air missile system, Pinaka multi-barrel rocket launchers, Swathi weapon locating radars, and Advanced Towed Artillery Gun Systems (ATAGS).



Key points:

- Strategic Pact: Signed an MoU in Yerevan focusing on defence research, development, innovation, and joint production.
- Key Signatories: Signed by India's Defence Secretary Rajesh Kumar Singh and Armenia's High-Tech Industry Minister Davit Tadevosyan.
- Expanding Procurement: Defence contracts between both nations have reached nearly USD 2 billion, featuring key Indian systems like Akash, Pinaka, and ATAGS.



दैनिक समसामयिक

DAILY

CURRENT AFFAIRS

MCQs

प्रश्नोत्तरी

Q1. अगस्त 2026 में भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा अनुसंधान, विकास, नवाचार और संयुक्त उत्पादन से संबंधित MoU किस शहर में हस्ताक्षरित किया गया?

- (a) बाकू (b) त्विलिसी
(c) य़ेरेवन (d) ताशकंद

Q2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की SEED योजना मुख्य रूप से किन समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई है?

- (a) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(b) अल्पसंख्यक समुदाय
(c) विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियाँ
(d) सीमावर्ती क्षेत्रों के जनजातीय समुदाय

Q3. एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का उद्घाटन 17 अगस्त 2026 को कहाँ किया गया?

- (a) शिमला (b) श्रीनगर
(c) देहरादून (d) लेह

Q4. अगस्त 2026 में JSSC-CGL सहित भर्ती परीक्षाओं में सुधारों की सिफारिश करने वाली समिति के अध्यक्ष के रूप में किस IAS अधिकारी को नियुक्त किया गया?

- (a) एल. खैंगटे (b) वंदना डडेल
(c) अविनाश कुमार (d) अमिताभ कौशल

Q5. SEMICON India 2026 के 5वें संस्करण का केंद्रीय विषय क्या है?

- (a) डिजिटल भविष्य को आकार देना: चिप्स से डिवाइस तक
(b) सिलिकॉन से सिस्टम तक: इकोसिस्टम का निर्माण
(c) भारत के 'टेकेड' को सशक्त बनाना: सेमीकंडक्टर विज्ञान
(d) ग्लोबल सप्लाइ चैन: रेत से सिलिकॉन तक

Q6. दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS की स्थापना किस वर्ष की गई थी?

- (a) 2008 (b) 2009
(c) 2010 (d) 2011

Q1. In August 2026, in which city was the MoU between India and Armenia on defence research, development, innovation, and joint production signed?

- (a) Baku (b) Tbilisi
(c) Yerevan (d) Tashkent

Q2. The SEED scheme of the Ministry of Social Justice and Empowerment is primarily aimed at the economic empowerment of which communities?

- (a) Scheduled Castes and Scheduled Tribes
(b) Minority Communities
(c) Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes
(d) Tribal Communities of Border Areas

Q3. Where was the Asian Open Short Track Speed Skating Trophy 2026 inaugurated on 17 August 2026?

- (a) Shimla (b) Srinagar
(c) Dehradun (d) Leh

Q4. In August 2026, which IAS officer was appointed as the chairman of the committee recommending reforms in recruitment examinations, including the JSSC-CGL examination?

- (a) L. Khaingte (b) Vandana Dadel
(c) Avinash Kumar (d) Amitabh Kaushal

Q5. What is the central theme of the 5th edition of SEMICON India 2026?

- (a) Shaping the Digital Future: From Chips to Devices
(b) Silicon to Systems: Building the Ecosystem
(c) Empowering India's 'Techade': Semiconductor Vision
(d) Global Supply Chain: From Sand to Silicon

Q6. In which year was the United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) established?

- (a) 2008 (b) 2009
(c) 2010 (d) 2011

Q7. रक्षा मंत्रालय द्वारा जनरल एटॉमिक्स के साथ 1,943 करोड़ रुपये का दो MQ-9B Sea Guardian लीज समझौता भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा के लिए किया गया?

- (a) भारतीय वायु सेना
- (b) भारतीय थल सेना
- (c) भारतीय नौसेना
- (d) भारतीय तटरक्षक बल

Q8. UNCCD COP17 के दौरान भारत की पहली 'Guide to Grasslands and Other Open Natural Ecosystems (ONEs) of India' कहाँ लॉन्च की गई?

- (a) नई दिल्ली
- (b) रियाद
- (c) ताशकंद
- (d) उलानबटार

Q9. 'अपराजिता - पारंग ला 2026' उच्च-ऊँचाई वाला ट्रेक किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है?

- (a) स्पीति घाटी और चांगथांग
- (b) किन्नौर घाटी और जंस्कार
- (c) कांगड़ा घाटी और करगिल
- (d) कुल्लू घाटी और लेह

Q10. राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के तहत 'राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार' किसे प्रदान किया गया?

- (a) भारतीय खेल प्राधिकरण, बेंगलुरु
- (b) टाटा स्टील स्पोर्ट्स अकादमी, जमशेदपुर
- (c) आर्मी पैरालंपिक नोड, पुणे
- (d) रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, नई दिल्ली

Q7. The ₹1,943 crore lease agreement signed by the Ministry of Defence with General Atomics for two MQ-9B Sea Guardian systems was made for which branch of the Indian Armed Forces?

- (a) Indian Air Force
- (b) Indian Army
- (c) Indian Navy
- (d) Indian Coast Guard

Q8. Where was India's first 'Guide to Grasslands and Other Open Natural Ecosystems (ONEs) of India' launched during UNCCD COP17?

- (a) New Delhi
- (b) Riyadh
- (c) Tashkent
- (d) Ulaanbaatar

Q9. The high-altitude trek 'Aprajita – Parang La 2026' connects which two regions?

- (a) Spiti Valley and Changthang
- (b) Kinnaur Valley and Zaskar
- (c) Kangra Valley and Kargil
- (d) Kullu Valley and Leh

Q10. Who was awarded the 'Rashtriya Khel Protsahan Puruskar' (National Sports Promotion Award) under the National Sports Awards 2025?

- (a) Sports Authority of India, Bengaluru
- (b) Tata Steel Sports Academy, Jamshedpur
- (c) Army Paralympic Node, Pune
- (d) Railway Sports Promotion Board, New Delhi

उत्तरमाला (Answer Key)

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| 1 | C | 2 | C | 3 | C | 4 | D | 5 | B | 6 | D | 7 | C | 8 | D | 9 | A | 10 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|

